मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता।

दुनिया के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है।

दुनिया को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा।

RN 42233

नई सीरीज नम्बर 11 | मई 1989 | 50 पैसे

आठ घन्टे काम का मतलब

तनखा इतनी होनी चाहिये कि एक परिवार के गुजारे के लिये परिवार के एक व्यक्ति को एक दिन में आठ घन्टों से ज्यादा काम नहीं करना पड़े—मजदूरों द्वारा उठाई इस माँग को सौ साल से ज्यादा हो गये हैं। आज पोजीशन क्या है ?

सरकारी कानून के मुताबिक आज यहाँ आठ घन्टे की ड्यूटी है—सरकारी कानून कितना-कलागु है इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। आइये आठ घन्टे ड्यूटी वालों पर नजर डालें। खुद सरकार ने 1957 में एक हिसाब लगवाया था। दादा-दादी तो हिसाब लगाने वालों को याद ही नहीं आये, बूढे माँ-बाप तक को परिवार के अपने हिसाब से निकालकर उन पूँजीवादी विद्वानों ने सिर्फ जिन्दा रहने के लिये जरूरी पति-पत्नी-दो बच्चों वाले तीन यूनिट के परिवार के लिये मजदूरी का तब हिसाब लगाया था। उस सरकारी हिसाब के मुताबिक आज एक मजदूर की तनखा कम से कम तीन हजार रुपये महीना होनी चाहिए। और हरियाणा सरकार ने चुनावी ढोल पीटा है : 800 का कानन बना कर उसने मजदूरों को स्वर्ग दे दिया है (मजदूरों को मिलें चाहे तीन-चार सौ)।

यह इसलिये है कि आज पति-पत्नी, दोनों का नौकरी करना जरूरी हो गया है। इसीलिये जहाँ आठ घन्टे काम का दिन की माँग करने वाली पीढी के मजदूर ओवर-टाइम करने से मना करते थे वहाँ आज मजदूर ओवरटाइम के लिये मक्खनबाजी तक करते हैं। फैक्ट्री में ड्यूटी के बाद आज मजदूर चार-आठ घन्टे पार्टटाइम या छोटे-मोटे धन्धे की फिराक में रहते हैं। जिन मजदूरों के बीबी-बच्चे गाँवों में हैं वे वहाँ खेती-क्यारी का काम करते हैं और जिनके बच्चे शहर में हैं वे फैक्ट्रियों में काम करते हैं या अपने रहने की जगह पर चप्पलों के फीते काटने—प्लास्टिक काटने-छाँटने—सिलाई आदि के फैक्ट्रियों के काम करते हैं या छोटे-मोटे धन्धों में जुटे रहते हैं। दिन तो आज भी 24 घन्टे का होता है पर एक परिवार आज रोज 26 घन्टे काम करता है। फिर भी मजदूरों के रहन-सहन का स्तर गिरता जा रहा है। और आठ घन्टे काम के दिन की माँग उठाने वाली पीढी के मजदूर से आज का मजदूर पचास गुणा प्रोडक्शन करता है।

पूँजीवाद के शुरू के उन दौरों को छोड़ कर जब मजदूर कम मिलते हैं, पूँजी के नुमाइन्दों की एक ही रट होती है : "आठ घन्टों की भी क्या जरूरत है, हमारी तरफ से तो तुम एक घन्टे भी काम मत करो !" दस्तकारी व किसानी को तबाह करता तथा नई-नई मशीनरी से सौ मजदूरों का काम चार मजदूरों से करवाने वाला पूँजीवाद का विकास लगातार पूंजी की जरूरत से ज्यादा काम की तलाश में घूमते लोगों को पैदा करता है। इसीलिये मजदूरों की तनखा बढाने की माँग का आज मैनेजर-ठेकेदार-छोटे मालिक ऐसे उत्तर देते हैं : "इतने ही पैसे देंगे। तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करो। अपना हिसाब ले लो। तुम्हारे सौ भाई यह काम करने के लिये गेट पर खड़े हैं।" सब जानते हैं कि काम नहीं का मजदूर के लिये मतलब भूखे मरना है। फिर भी, मजदूरों को समझ लेना चाहिये कि पूँजी के विकास के साथ दुनिया-भर में सड़कों पर धूल फाँकती बेरोजगारों की लगा तार बढती फौज जहाँ अलग-अलग पूँजी के नुमाइन्दे का अमोघ अस्त्र है और अलग-अलग मजदूर की लाचारी, वहीं मशीन चला रहे और सड़क नाप रहे मजदूरों की एकता सम्पूर्ण पूँजीवादी व्यवस्था को उड़ा देने की ताकत वाली बारूद है।

पूँजीवाद में मजदूरों की हालत का गिरते जाना इस व्यवस्था का नियम है। कुर्सियों पर बैठने वालों को बदलने से इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आठ घन्टे काम की माँग करने वाले हमारे पुरखों ने साँस लेने की फुरसत के लिये संघर्ष किया था। लेकिन आज दुनिया के हर हिस्से में बेरोजगारों की फौज बढती जा रही है और मजदूरों की असल तनखायें घटाई जा रही हैं तथा उन पर वर्क लोड बढाये जा रहे हैं। पूँजी के नुमान्दों की मजदूरों की हालत गिराने की कोशिशों के खिलाफ तो मजदूरों को संघर्ष करने ही हैं, असल में आज सम्पूर्ण पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़-फेंकने का संघर्ष मजदूरों के लिये जिन्दगी और मौत का सवाल बन गया है—आठ घन्टे काम के दिन का आज यही मतलब है, मई दिवस का अब यही अर्थ है।

—×—

हरियाणा सरकार ने कानून बनाया है कि किसी भी मजदूर की कम से कम तनखा 800 रुपए महीना होगी। महीने में चार दिन की छुट्टी भी होती हैं इसलिए एक दिन की ध्याड़ी 30 रुपये 77 पैसे बनती है। दुकान पर काम करने वाला मजदूर हो चाहे कैंटीन का वर्कर, वर्कशाप में काम करने वाला मजदूर हो चाहे ठेकेदार का वर्कर—सरकारी कानून के मुताबिक रोजनदारी पर उसकी ध्याड़ी कम से कम 30 रुपये 77 पैसे है और महीने के हिसाब से कम से कम 800 रुपए है। पूँजीवादी कानूनों से जहाँ कहीं मजदूरों की थोड़ी-बहुत हालत सुधर सकती है वहाँ आमतौर पर वे कागजी घोड़े ही रहते हैं। ऐसे पूँजीवादी कानूनों को लागू करवाने के लिए मजदूरों के संघर्ष जरूरी हैं। हरियाणा सरकार के कानून अब तक 542 या 625 की बात करते रहे हैं पर अभी भी फरीदाबाद में ही दसियों हजार मजदूरों को 300-400 रुपये महीने में खटना पड़ रहा है।

पूँजीवादी चुनावी ड्रामों में मूसलचन्द बनना ही मजदूरों की राह है। इस तरह से कानपुर में मजदूरों ने पांच दिन रेलें रोककर एक जीत हासिल की है। लोहा गर्म हो रहा है, पूँजीवादी गुटों की पूँछ बनने की बजाय आओ हथौड़ा बनकर चोट मारें। इसके लिए आओ उन सब जगहों की जानकारी इकट्ठी करें जहाँ 800 रुपये महीना या 30 रुपए 77 पैसे रोज की ध्याड़ी नहीं दी जा रही और साथ-साथ नए तनखा कानून को लागु करवाने के रास्तों पर मिल-बैठकर विचार करें। बाटा चौक के पास आटोपिन झुग्गियों में मजदूर लाइब्रेरी में मिलें।

मजदूरों को खुद कदम उठाने होंगे। बिचौलियों पर आस लगाना मजदूरों की बरबादी की राह है।

तनखा नहीं, मोटरसाइकिल लो !

प्रोविडैंट फन्ड जमा न करना, हाउसिंग के नाम पर मजदूरों से लिये पैसों को हाउसिंग प्लाट बेचने के बाद भी न लौटाना, सोसाइटी आदि के पैसों का हिसाब न देना तो गेडोर मैनेजमेंट के लिये छोटी बातें हैं, टाल-मटोल करके चार साल में उसने इस समय मजदूरों की सात महीनों की तनखा भी इक्ट्ठी कर ली है। आठ-दस महीने पहले मैनेजमेंट ने घोषणा की थी कि 200 रुपये महीने की किस्तों में वह मजदूरों के पैसे दे देगी। पर 200 की किस्त देने में भी उसने हेरा-फेरी की और इस समय गेडोर के मजदूरों के तनखा के 8 से 10 हजार रुपये प्रति मजदूर बकाया हैं। इस पर मजदूरों के असन्तोष को कम करने के लिये यूनियन लीडरों ने तुर्रा छोड़ा—बकाया वेतन के बदले में मजदूर मोटरसाइकिल या स्कूटर ले लें ! जान लें कि इस समय वाले यूनियन लीडर उस समय फरीदाबाद सीटू प्रेसीडेंट के लठैत थे जब 1984 में गेडोर मैनेजमैंट की छँटनी पालिसी लागु करने के लिये सीटू प्रैसीडैंट ने मार-मार कर गेडोर के डेढ हजार मजदूरों से इस्तीफे लिखवाये थे। वैसे, बदनामी के ज्यादा फैलने पर सीटू की दिल्ली कमेटी ने फरीदाबाद सीटू प्रैसीडैंट और जोइन्ट सैक्रेटरी, जो कि गेडोर यूनियन के प्रेसीडैंट और जनरल सैक्रेटरी भी थे, उन्हें 1984 के उनके करमों के लिये 1987 में सीटू से निकाला।

इस समय गेडोर के बहुत से मजदूर यह सोच कर कि मैनेजमेंट से जो कुछ भी हो सके झटक लो, मोटरसाइकिल-स्कूटर लेकर बेच देने की सोच रहे हैं। मजदूरों को समझ लेना चाहिये कि अगर मोटरसाइकिल-स्कूटर वाली स्कीम लागु भी हुई तो बैंक का कर्ज मजदूर के नाम पर होगा और मैनेजमेंट सिर्फ जमानती बनेगी। ऐसे में एक बात तो यह है कि गाड़ी के कागजात बैंक के पास रहेंगे इसलिये उसे औने-पौने भाव में ही बेचा जा सकेगा। दूसरी बात ज्यादा गम्भीर है—टाइम पर किस्त जमा न करने पर बैंक जुर्माना लगायेगा और मजदूर को इसका पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वह तो किस्त की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की सोचेगा। जो मैनेजमेंट हजारों मजदूरों की आँखों के सामने उनकी बकाया तनखा की किस्त देने में ही टाल-मटोल करती है वह बैंक के कागज-पत्र के जवाब में चार-छह महीनों में एक किस्त जमा कर देगी तो भी शुक्र मनाने वाली बात होगी। वैसे भी, जुर्माना तो मजदूर के लगेगा और ब्याज समेत इसे बैंक उसकी सर्विस आदि से वसूल लेगा। 1976 में कुछ मजदूरों को न्यू बैंक से

हमारे लक्ष्य हैं—1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुँचाने के प्रयास करना। 2. पूँजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनिया के मजदूरों की एकता के लिए काम करना और इसके लिए आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बँटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिए काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिए काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को तालमेल के लिए हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिए बेझिझक मिलें। टीका-टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

सम्पर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन० आई० टी० फरीदाबाद—121001

दो हजार का हाउसिंग लोन दिलवाने में गेडोर मैनेजमेंट इसी तरह जमानती बनी थी। उन मजदूरों की तनखा से मैनेजमेंट किस्त के पैसे काट लेती थी पर न्यू बैंक में तीन महीने बाद ही जमा करती थी। बैंक ने देरी से किस्ते देने पर जुर्माने लगाये जो उन मजदूरों को भरने पड़े।

बिचौलियों केशोशों में उलझने की बजाय मजदूरों को अपनी तनखा और अन्य पैसों के लिये मिल कर कदम उठाने होंगे—और अभी। मैटल बाक्स ने 15 करोड़ की साख पर बैंकों से 45 करोड़ रुपये कर्ज ले लिया था, गेडोर उर्फ झालानी टूल्स में तो और भी ज्यादा गड़बड़ है। मैनेजमेंट पर बकाया अपने करोड़ों रुपयों के लिये मजदूर अभी ही कदम नहीं उठायेंगे तो बाद में बदहवासी में तो उन्हें उल्लु बनाने के लिये तरह-तरह के ड्रामे शुरू हो जायेंगे।

—×—

दुनिया में मजदूरों के संघर्ष

कोरिया

कौन ड्रामेबाज आज किस पार्टी में है और कल के अपने दल के बारे में क्या कह रहा है वाली बकवास से अखबार भरे रहते हैं। हिन्दी आदि के जिन अखबारों को मजदूर पढ सकते हैं उनमें पूंजीवादी राजनीति की कीचड़ के साथ-साथ पूंजीवादी व्यवस्था की हत्या-बलात्कारी उपज की बदबू से पन्ने-दर-पन्ने भरे रहते हैं। मजदूरों के नाम पर बिचौलियों के फर्जी संघर्षों को भी इस पूंजीवादी कूड़े-कचरे में स्थान मिलता है। पर मजदूरों के वास्तविक आन्दोलनों की जानकारी यह अखबार आमतौर पर नहीं देते। और जब मजदूर संघर्ष का उभार इनको चुप्पी तोडने को मजबूर कर देता है तब यह एक तरफ नंगे हो कर दमन की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ संघर्ष के मजदूर वर्गीय सार को छिपाने के लिये तोड़-मरोड़ का सहारा लेते हैं। कोरिया में मजदूरों के विशाल संघर्ष के बारे में हिन्दी अखबारों ने तो अपनी चुप्पी ही नहीं तोड़ी। और यहां के अंगरेजी अखबारों ने उसकी मामूली-सी चर्चा तब की जब 109 दिन से चल रही मजदूर हड़ताल को तोड़ने के लिये 30 मार्च को 14,500 हथियारबन्द सिपाहियों के हमले के खिलाफ 9 अप्रैल को विद्यार्थियों ने जलूस निकाले। पूंजी के नुमाइन्दों के कुछ ज्यादा तेज-तर्रार विदेशी अखबारों ने कोरिया में मजदूरों के उभार की चीर-फाड़ की है और आने बाले दिनों में मजदूर आन्दोलन के बढने को अनिवार्य समझ कर उससे निपटने के तरीकों पर विचार किया है। यहाँ इस्तेमाल सामग्री हमने दि एशियन वाल स्ट्रीट जरनल, न्यूजवीक और बिजनेस वीक से ली है।

पूंजी के नुमाइन्दों का एक धड़ा मजदूरों के शोषण को बेरोकटोक करने के लिये नंगे दमन की वकालत करता है तो उनका दूसरा धड़ा नंगे दमन से पनपते विस्फोट के खतरे से चिन्तित रहता है और पुचकार कर मजदूरों की चमड़ी उतारने की दलीलें देता है। हालात के अनुसार एक फैक्ट्री से लेकर एक देश तक में पूंजी के नुमाइन्दों के नरम-गरम हथकन्डों में उलट-फेर होती है। पूंजी के प्रतिनिधि इन फेर-बदलों को पालिसियों में परिवर्तन के रूप में देखते हैं पर वास्तव में यह मजदूरों के प्रतिरोध की प्रतिक्रियायें मात्र होते हैं। और मजदूरों के प्रतिरोध का स्तर पूंजीवादी व्यवस्था के संकट के स्तर से जुड़ा है। पूंजीवाद के संकट समाज की गति के उन नियमों की उपज हैं जिन पर पूंजी के नुमाइन्दों का कोई बस नहीं है। इतिहास के एक खास चरण पर ढाई सौ साल पहले पैदा हुई मजदूर लगा कर मंडी के लिये पैदावार करने वाली उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति अस्सी-नब्बे साल से अपने पतन के दौर में है। इससे पूंजीवादी व्यवस्था के संकट इस हद तक बढ गये हैं कि एक तरफ पूंजी के नुमाइन्दे टाइम-ब-टाइम दुनिया को खून की नदियों में डुबोते हुये मानव विनाश की ओर बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मजदूरों के संघर्ष अपने खून से रंगे झन्डे को गिर-गिर कर उठाते हुये विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्प, विश्व साम्यवादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में, रूस में मजदूरों की बगावत के डर से भयभीत पूंजी के नुमाइन्दों में गोर्वाचोव धड़े का ऊपर आना और दुनिया को राह दिखा चुके मजदूरों के वारिसों को गोर्वाचोव द्वारा जनतन्त्र की टाफी पकड़ाना या फिर अमरीकी फोजों के साये में पल रहे दक्षिण कोरिया में पूंजी के नुमाइन्दों द्वारा तीस साल हाथों में नंगी तलवार थामकर अब जनतन्त्र का नाटक करना—इतिहास के नजरिये से यह बचकाने ढकोसले मात्र हैं। इस पीढी के मजदूरों की यह बदकिस्मती है कि पूंजीवादी प्रहसन आज भी जारी है, लेकिन पूंजीवाद को दफनाने का काम अगर हम कर लेंगे तो यह हमारी खुशकिस्मत भी हो सकती है।

दक्षिण कोरिया में नंगे दमन के पक्षधर पूंजी के नुमाइन्दों ने वर्षों मजदूरों-मेहनतकशों के खून से अपने हाथ रंगे पर फिर भी वहाँ मजदूरों के आन्दोलन बढने लगे। इस पर बगावत के बढते खतरे को भाँप कर 3 साल पहले दक्षिण कोरिया में पूंजी के नुमाइन्दों में उलट-फेर हुई। जनतन्त्र का नाटक करने का फैसला हुआ और खूनी राष्ट्रपति माफी माँग, बुद्ध भिक्षु बन कर इहलोक के अपने कुकर्मों से मुक्त हो गया। धर्म लुटेरों के बड़े काम का है, मजदूरों-मेहनतकशों के लिये धर्म अफीम है।

चुनाव का नाटक और ढोल-नगाड़ों के साथ ओलम्पिक खेलों का ड्रामा भी कोरिया में हुआ पर मजदूर आन्दोलन है कि बढता ही जा रहा है। 1987 में मजदूरों की तनखा 13·5 प्रतिशत और 88 में 14 प्रतिशत बढानी पड़ी। इस समय दक्षिण कोरिया में मजदूर का औसत वेतन सात हजार रुपये महीना है और इस साल की पहली तिमाही में ही वहाँ 300 से ज्यादा हड़तालें हो चुकी हैं जो कि पिछले वर्ष की इसी समय हुई हड़तालों से दुगनी हैं। वहाँ के मंत्री भी मान रहे हैं कि लक्षण मजदूर आन्दोलन के बढने के हैं।

पूंजी के अमरीकी धड़े के इस चमत्कार में मजदूरों से निपटने के लिये जोर-शोर से तैयारियाँ हो रही हैं। मजदूरों को सबक सिखाने के लिये सरकार अपने हमले ध्यान से चुन कर उन हड़तालों पर कर रही है जिनसे आम आदमी परेशान होता है—16 मार्च को राष्ट्रपति ने हथियारबन्द पुलिस का इस्तेमाल करके राजधानी में 5 हजार अन्डरग्राउन्ड रेल मजदूरों की हड़ताल तोड़ी। सरकार ने प्रतिज्ञा की है कि वह यूनियनों को जापानी यूनियनों की तरह सरकार व मैनेजमेंट के पाकेट संगठन बना देगी। जापान में तो मैनेजमेंटों ने यूनियनों को अपनी जेबों में रखा हुआ है पर कोरिया में ऐसा करने में कुछ समय लग रहा है क्योंकि 3 साल पहले तक कोरिया में मैनेजमेंटें यूनियनों को काम नहीं करने देती थी। कोरिया में भी यूनियनों को पूंजीवादी औजार बनाने के लिये सरकार उन यूनियनों को हथियारबन्द पुलिस के जरिये कुचल रही है जो सरकारी लीक पर नहीं चलती। इसमें सरकार सफल हो रही है और अभी ही बहुत से मजदूर कोरिया की ट्रेड यूनियन फेडरेशन को सरकारी मान कर उससे कटने लगे हैं। और इसमें पूंजीवाद को खतरे हैं क्योंकि फिर पूंजी के लिये मजदूरों को कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये वहाँ विरोधी पूंजीवादी पार्टियाँ भारत की तरह ही दिखावटी लड़ाकू यूनियनों को खड़ा करने की सोच रही हैं।

कोरिया में मैनेजमेंटें कहती हैं कि एक महीने की हड़ताल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पर वे दो या तीन महीनों की हड़ताल नहीं झेल सकती। और इधर हड़तालें लम्बी होने लगी हैं। इसलिये कोरिया सरकार के अफसरों ने हड़ताल की शिकार कम्पनियों को पैसे देने और टैक्सों में उन्हें छूट देने का फैसला किया है। मजदूरों के खिलाफ सब जगह पूंजी का पूरा तन्त्र एक हो जाता है इसलिए मजदूरों के लिए जरूरी है कि वे आजु-बाजु के मजदूरों के संघर्षों में शामिल होकर पूंजी के खिलाफ मजदूरों के मोर्चे को मजबूत करें।

और, कुछ कम्पनियों ने मजदूरों पर हमले करने के लिए कुसाडे यानि दाल फ्राई गुण्डों की भर्ती शुरू की हुई हैं।

दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगर, उलसान की सबसे बड़ी कम्पनी, ह्यून्दाई भारी उद्योग में 109 दिन से जारी जुझारु हड़ताल को 14,500 हथियारबन्द सिपाहियों की मदद से 30 मार्च 88 को तोड़ने के बाद ऊपर कही बातों में तेजी आई है। हमले के दो हफ्ते बाद, 14 अप्रैल तक 20,324 मजदूरों में से आधे भी काम पर नहीं आये थे और काम नहीं के बराबर हो रहा था। 700 मजदूर गिरफ्तार थे, फौज गश्त कर रही थी और पुलिस अगुआ हड़ताली मजदूरों को ढूंढ़ रही थी। तनाव बना हुआ है और बहुत से लोग हालात को तूफान से पहले की शान्ति मान रहे हैं। मैनेजमेंट के 56 उच्च अधिकारी मजदूरों को पुचकारने में दिन-रात एक कर रहे हैं। समुद्री जहाज बनाने वाली ह्यून्दाई भारी उद्योग में 600 ठेकेदार भी हैं और कोरिया में ढाई लाख मजदूर इस कम्पनी का काम करते हैं। ह्यून्दाई में 87 और 88 में भी उग्र हड़तालें हुई थी। इस बार मजदूरों ने इन माँगों के लिये हड़ताल शुरू की थी : एक महीने का अतिरिक्त बोनस, प्रोडक्शन इन्सैन्टिव भत्ता, अधिक पेन्शन व छँटनी भत्ता और हफ्ते में 48 की बजाय 44 घन्टे काम। और, 11 अप्रैल को अमरीका के टैन्डी कारपोरेशन की कोरिया में फैक्ट्री की महिला मजदूरों ने मैनेजर का घेराव शुरू किया। टैन्डी कारपोरेशन ने फैक्ट्री बन्द करके 900 महिला मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। ऊपर से इन मजदूरों की दो महीनों की तनखा और छँटनी भत्ता भी नहीं दिया। महिला मजदूरों द्वारा घेराव के बाद मैनेजमेंट ने कहा कि पैसे देने में देरी कम्प्यूटर की गड़बड़ से हुई है।

—×—

***मजदूर जमात**, अंक 10, फरवरी-मार्च 1989 :

"सवाल—टर्नर भाई, आप निपुण मजदूर हो। भला आपकी लाइन के और कौन-कौन से मजदूर निपुण गिने जाते हैं ?

जवाब—हम खरादिये, फिटर, मिलिंग मैन, मशीनमैन, मोल्डर, गराईंडर, वैल्डर, मिस्त्री, इलैक्ट्रीशियन इत्यादि लगभग सभी निपुण मजदूर होते हैं।

सवाल—आपकी योग्यता क्या है ?

जवाब—मैंने मैट्रिक पास कर, दो साल का आई० टी० आई० कोर्स पास किया है। बाकियों की भी लगभग इतनी ही योग्यता होती है।

सवाल—फैक्ट्री में मालिक आपको कितना वेतन देता है ?

जवाब—मेरे को 900 रुपये महीना मिलता है। वैसे आमतौर पर 600-700 से 1000-1100 तक चलता है।

सवाल—वैसे, स्कूल मास्टर की योग्यता क्या होती है ?

जवाब—उसका भी मैट्रिक करने के बाद जे०बी०टी० का कोर्स शायद दो साल का ही होता है।

सवाल—भाई साहब, जे०बी०टी० मास्टर कितना वेतन पाते हैं ?

जवाब—यही कोई 1700-1800 रुपये।

सवाल—क्या आपको मालूम है कि मास्टर वेतन में बढोतरी के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं ? गत दिनों उन्होंने स्कूलों में सप्ताह भर के लिये काम ठप्प करके रखा ?

जवाब—सुना तो था जी।

सवाल—बिजली वाले, रोडवेज वाले ड्राइवर-कंडक्टर भी वेतन बढ़ोतरी इत्यादि माँगों के लिए पंजाब-भर में हड़तालें करके संघर्ष के मैदान में निकल आये हैं···

जवाब—हाँ, हाँ, रोडवेज वालों ने तो एक भी सरकारी बस अड्डे से बाहर नहीं निकाली। पूरे दिन चक्का जाम।

सवाल—1700-1800 वाले मास्टर भी अगर तंग हैं, 1500-1600 वाले बिजली वाले तथा ड्राइवर-कंडक्टर इत्यादि भी मंहगाई के सताये हुये हैं, वेतन बढ़ोतरी तथा और सुविधाओं के लिए हड़तालें कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तो आप 900-1000 वाले निपुण···?···?

जवाब—ह-ह-हम ?"

पंजाबी और हिन्दी में छपने वाली 'मजदूर जमात' के असल में मजदूर जमात की पत्रिका बनने की हम कामना करते हैं।

सम्पर्क—नरेन्द्र, सम्पादक मजदूर जमात, गली नम्बर 14 प्रताप मार्केट, गिल रोड, लुधियाना (पंजाब)।

स्वत्वाधिकारी व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अशोक कम्पोजिंग एजेन्सी द्वारा, मानस प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली-110031 में मुद्रित।